



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 23, 2007/श्रावण 1, 1929

No. 205]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 23, 2007/SRAVANA 1, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेशी व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2007

सं. 27 (आर ई-2007)/2004—2009

फा. सं. 01/94/180/781/एएम07/पीसी-1.—शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जो कि 1-5-2006 से लागू हुई थी। व्यापार और उद्योग जगत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं - कि स्कीम लागू होने के शुरू में निर्यातक सीमाशुल्क के फील्ड फॉर्मेशन के साथ सॉफ्टवेयर पैकेज की उपलब्धता के लिए स्कीम के तहत अपने शिपिंग बिल प्रस्तुत करने में असमर्थ थे।

- निर्यात कार्गो के मुक्त संचालन को आसान बनाने के लिए, विभिन्न पतनों पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र स्कीम के तहत पोतलदान की अनुमति 30-4-2006 के बाद भी दे दी। बाद में, सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने डी एफ आर सी शिपिंग बिलों के तहत प्रस्तुत इन शिपिंग बिलों को डी एफ आई ए स्कीम शिपिंग बिलों में परिवर्तित कर दिया।
- व्यापार और उद्योग जगत से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि ऐसे परिवर्तित शिपिंग बिल डी एफ आई ए की मंजूरी के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्वीकृत नहीं किए जा रहे।
- उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और विदेश व्यापार नीति 2004—2009 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा

क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा ऐसे शिपिंग बिलों पर कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अधिसूचित करते हैं : निम्नलिखित मामलों में क्षेत्रीय प्राधिकारी डी एफ आई ए स्कीम के लाभ की अनुमति देगा :

क. जहाँ आवेदक फर्म ने सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा डी एफ आई ए शिपिंग बिलों में विधिवत् परिवर्तित शिपिंग बिल प्रस्तुत किए हों; और

ख. जहाँ डी एफ आई ए शिपिंग बिलों पर फाइल संख्या का पृष्ठांकन न किया जा सका हो, ऐसे मामलों में क्षेत्रीय प्राधिकारी ई ओ डी सी में अथवा हस्तान्तरणीय पत्र में विशिष्ट पृष्ठांकन करेगा ताकि ऐसे डी एफ आई ए के प्रति आयातों की अनुमति देने से पहले पंजीकरण पत्र पर सीमाशुल्क प्राधिकारी अपने रिकार्ड से शिपिंग बिलों के विवरण की जाँच कर सकें।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 23rd July, 2007

No. 27 (RE-2007)/2004—2009

F. No. 01/94/180/781/AM07/PC-I.—Attention is invited to the Duty Free Import Authorisation (DFIA) Scheme, which came into operation w.e.f. 1-5-2006.

Representations have been received from trade and industry that in the beginning of the operation of the Scheme, exporters were unable to file their shipping bills under the Scheme for want of availability of software package with the field formations of Customs.

2. To facilitate free movement of export cargo, Customs Authorities at various ports allowed the shipment under Duty Free Replenishment Certificate (DFRC) Scheme even beyond 30-4-2006. Subsequently, Customs Authorities converted these shipping bills filed under DFRC shipping bills into DFIA Scheme shipping bills.
3. Representations have also been received from trade and industry that such converted shipping bills are not being accepted by the Regional Offices of DGFT for grant of DFIA.
4. In view of the above consideration and in exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the

following procedure for processing of such shipping bills by the Regional Authorities:

The Regional Authorities shall allow the benefit of DFIA Scheme in following cases of :

- (a) Where the applicant firm has presented Shipping Bills duly converted by the customs authorities to DFIA shipping bills; and
- (b) Where the file number could not be endorsed on the DFIA shipping bills, in such cases the Regional Authority shall make a specific endorsement in EODC or the transferability letter so that the customs authorities at the Port of Registration can verify the details of the shipping bills from their records before allowing imports against such DFIA's.

This issues in Public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign
Trade and ex-officio Addl. Secy.